भारत में आईएफएससी की कारोबारी क्षमताओं के मैक्रो एवं माइक्रो संचालक*

उर्जित आर. पटेल

ए. प्रस्तावना

1. आज हम यहां जीआईएफटी(गिफ्ट) की स्थापना और उसकी सफलता को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जीआईएफटी(गिफ्ट) भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र(आईएफएससी) है जो पूरे विश्व में कारोबार करने केलिए विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लोग तथा प्रौद्योगिकी को एक प्लेटफार्म पर ले आया है। यह सब-कुछ मिलाकर एक ऐसा आधुनिक आर्थिक अंचल है जो विश्व स्तरीय फर्मों को वित्तीय सेवाओं के लिए भारत की बृहत् एवं बढ़ती हुई मांग के प्रति प्रतिस्पर्धी पहुंच उपलब्ध कराती है।

2. पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का ऐतिहासिक रूप से आविर्भाव, आर्थिक एवं राजनैतिक संगम से हुआ है। आधुनिक दौर में जहां प्रमुख केंद्रों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के प्रवाह से अपनी वित्तीय संस्थाओं एवं लिखतों को जोड़ लिया है, वहीं वे मेज़बान देशों की आर्थिक संवृद्धि तथा विकास के वाहक के रूप में देखे जा रहे हैं।

3. उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आईएफएससी के कार्यों को नियंत्रित करने वाला रेगुलेटरी ढांचा सुविचारित रूप से बनाया गया हो, ऐसे सिद्धांतों पर आधारित हो जिससे कारोबार करने में आसानी पैदा हो, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के अनुरूप हों, तथा कुशल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की ओर उन्मुख हों। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न कार्यक्षेत्र हैं जिनका ख़याल रखा जाना है वे हैं - पंजीकरण तथा नये प्रतिभागियों के लिए अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया, रेगुलेशन, पर्यवेक्षण तथा वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं का समाधान एवं विवादों का निपटान किया जाना।

4. 2008 के विश्व के वित्तीय संकट के बाद संभवत: गिफ्ट शहर में आईएफएससी इस प्रकार का पहला केंद्र है जिसकी शुरुआत की गई है। संकट काल के बाद आईएफएससी द्वारा अपनाए गए रेगुलेटरी दर्शन पर हलके फुलके तरीके से कुछ हद तक प्रश्न किए गए हैं। लेकिन, गिफ्ट शहर के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस संबंध में और ज्यादा सवालों से बचने के लिए उसने यथोचित सबक हासिल कर लिया है।

5. हाल के दिनों में भारतीय रिज़र्व बैंक समस्त आईएफएससी हितधारकों के साथ विभिन्न विषयों पर गिफ्ट को विकसित करने के संबंध में जुटकर सहायता करता रहा है।

6. आज हम यह देख रहे हैं कि प्रमुख आईएफएससी के बीच बड़ी तीव्र स्पर्धा हो रही है और वे यह कोशिश कर रहे हैं अनेक कारोबारी क्षेत्रों के लिए स्वयं को स्थापित कर लें, तथा अपने कारोबार की क्षमता को बढ़ा लें, और यही आज के इस सेमिनार का थीम है। सामान्य बातों के अलावा इसके दो अन्य आयाम भी हैं जैसे उनसे जुड़ी हुई नीतियों के अनुरूप बृहत् आर्थिक वातावरण तथा आईएफएससी क्षेत्र के लिए विशिष्ट स्वरूप का माइक्रो ईकोसिस्टम का होना।

बी. मैक्रो

7. जहां आज हम गिफ्ट की सफलता का जश्न मना रहे हैं वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि इसकी आगे की तरक्की अन्य बातों के साथ-साथ उस घरेलू मैक्रो स्थिरता के वातावरण पर आधारित होगी जिसे हमने पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रमुख क्षेत्रों में हासिल किया है। हमें इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि हमने जो बनाया है और जो हासिल किया है उसे बनाए रखें। हमारे सुदृढ़ मैक्रो-आर्थिक प्रबंधन की साख इसी पर टिकी हुई है। इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो हम पाते हैं कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इससे दो महत्वपूर्ण संक्रमण जुड़े हुए हैं। एक तो यह कि अमरीका में राजकोषीय, मौद्रिक एवं व्यापार की नीतियों का पुन: समरूपण किया जाना जिसने पिछले दो महीने में पहले ही विश्व अर्थव्यवस्था में काफी वित्तीय अस्थिरता पैदा कर रखी है। यहां तक कि इससे नाफ्टा का भी दामन नहीं बच सका है। अमरीका के व्यापार के भागीदार, खासतौर से उभरते बाज़ार जैसे भागीदारों को तो पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। और यह सब अमरीका में इस महीने के आखिर में नई सरकार के सत्ता संभालने से पहले घटित हुआ है। और दूसरी जो संक्रमण की स्थिति थी वह नि:संदेह चीन में घरेलू उपभोग एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति निवेश एवं निर्यात को देखते हुए संवृद्धि के संचालकों को पुन: संतुलित करने की प्रक्रिया का अपनाया जाना रहा है। इनमें से एक के संक्रमण की स्थिति तो स्वागत योग्य है किंतु दूसरी उतनी नहीं है।

8. हमारे लिए भारत में अच्छी नीति बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बहुत आसान है कि मैक्रो आर्थिक स्थिरता से हमने जो हासिल किया है उसे बड़ी आसानी से गंवा दिया जाए। लेकिन उसे वापस प्राप्त करना मुश्किल भी है और जल्दी हसिल नहीं होती है। इस संदर्भ में हमने क्या सीखा कि हमारी नीति किस प्रकार की होनी चाहिए?

* डॉ. उर्जित पटेल, गवर्नर द्वारा 11 जनवरी 2017 को गांधीनगर, गुजरात में दिया गया भाषण

9. सबसे पहली बात यह है कि मौद्रिक नीति के ढांचे को क़ानूनी समर्थन प्राप्त है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति बनाए रखने का अधिसूचित लक्ष्य है जिसके के लिए छह सदस्यों की एक मौद्रिक नीति समिति बनाई गई है और उसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जितनी भी प्रगति अब तक हो चुकी है उसे ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य को प्राप्त करना है जो टिकाऊ बना रहे। मौद्रिक नीति के अलावा, मुद्रास्फीति को थोड़ा सा नहीं, बल्कि काफी कम करने में जो स्थिति प्राप्त की जा सकी है उसमें सरकार की नीतियों का समर्थन रहा है, खासतौर से वर्ष 2014 के बाद से अतिसक्रिय खाद्यान्न का प्रबंधन किया जाना।

10. सार्थक ब्याज दर ढांचा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि मुद्रास्फीति कम एवं स्थिर हो अथवा प्रणाली इस प्रकार की हो कि जिसमें बचतकर्ता एवं निवेशकों द्वारा लिए गए निर्णय अर्थव्यवस्था में क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने में सहायक बन सकें और जिनके निवेश की दर इतनी बढ़े जो संवृद्धि के लिए बेहतर परिणाम दे सके। साथ ही, हमें इस बात पर ज़ोर देते रहना होगा कि इसमें नमनीयता पैदा हो, मौद्रिक नीति आसानी से लागू हो सके तथा प्रशासनिक दरों सहित नीतिगत दरों के परिवर्तन एवं अन्य दरों के बीच फार्मूलागत लिंकेज को बेहतर बनाया जाए। तात्पर्य यह है कि इस समय इस प्रकार के कुछ समायोजन तदर्थ आधार पर किए जा रहे हैं। ये चीजें स्वत: ही पूर्वानुमानों को बेहतर बनाएंगी एवं आर्थिक एजेंट उनके आधार पर बेहतर दीर्घकालिक निर्णय ले सकेंगे।

11. इसके अतिरिक्त, जहां थोड़ी सी सरकारी गारंटी तथा सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता से मदद पहुंच सकती है, वहीं ब्याज दर को घटाते हुए सहायता पहुंचाने तथा बड़े ऋणों की गारंटी से वित्तीय संसाधनों का इष्टतम आबंटन बाधित हो सकता है तथा नैतिक खतरा बढ़ सकता है। इन सबके लिए अधिदेश कम होने चाहिए तथा रेगुलेटरी ढांचे के भीतर न्यायसंगत तरीके से ज़रूरत पड़ने पर ही दिया जाना चाहिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसका सुझाव दिया था। गारंटी से सरकार की आकस्मिक देयताएं बढ़ जाती हैं, तथा उसकी स्वयं की उधारी के जोखिम प्रीमिया को बढ़ा देती हैं। दरअसल गारंटी से आखिरकार महत्वपूर्ण क्षेत्र के मसलों को सुलझाने में इसकी सीमित उपयोगिता ही होती है। उदाहरण के लिए, लघु स्तर के उद्यमों केलिए शायद निकासी हेतु गैर-आर्थिक तथा लेनदेन संबंधी लागतें, निरीक्षण एवं कराधान नौकरशाही से जुड़े मामले कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

12. दूसरी बात यह है कि 2013 से केंद्र सरकार, राजकोषीय समेकन के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलती जा रही है। तब भी आईएमएफ डाटा के अनुसार सामान्य सरकार का घाटा (अर्थात् केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उधार दोनों मिलाकर) जी-20 देशों में सबसे अधिक है। इसी के साथ-साथ कुछ ने यह दिखाया है कि जीडीपी की तुलना में सरकारी कर्ज के अनुपात का स्तर इतना है जो क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाने के मार्ग में बाधा बन रहा है। जैसे-जैसे हम प्रगति के मार्ग पर बढ़ेंगे हमें इन तुलनात्मक अध्ययनों एवं तथ्यों को ध्यान में लेना होगा। खासतौर से इससे हम जोखिमों को बेहतर तौर पर स्वयं नियंत्रित कर सकेंगे तथा वित्तीय अस्थिरता को दूर कर सकेंगे। बाहर की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए जिसका उल्लेख मैंने पहले ही किया है, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।

13. ज्यादा से ज्यादा उधार लेना तथा सरकारों द्वारा भावी पीढ़ी के संसाधनों को अभी से खाली कर देना दूरगामी संवृद्धि केलिए शार्ट-कट नहीं है। बजाय इसके, भारतीय संवृद्धि के लिए संरचनात्मक सुधार एवं सरकारी खर्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर पुन: ले जाने महत्वपूर्ण होगा जिससे लंबे समय तक फायदा हासिल हो सकेगा। सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना, खासतौर से रेलवे एवं शहरी एमआरटीएस में निवेश करने से लागतें कम होंगी तथा उत्पादकता बढ़ेगी साथ ही इससे हमारा तेल के आयात का बिल घटेगा, और संपार्श्विक फायदे के रूप में हमारे शहरों की वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

14. तीसरी बात सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुन: पूंजी प्रदान करते रहने के संबंध में है। एक सुव्यवस्थित पूंजी वाली घरेलू बैंकिंग प्रणाली से विभिन्न प्रकार के हितधारकों को यह सहूलियत मिलती है कि वे आफशोर आईएफएससी के साथ भी कारोबार सहज रूप से कर सकेंगे। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू बैंकिंग प्रणाली की पूंजी के पर्याप्त प्रावधानों केलिए किए जाने वाले उपायों में भारत से बाहर आकर्षक वित्तीय केंद्र विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बैंक जी-20 एवं बीसीबीएस के सदस्य के रूप में पूंजी के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना जारी रखें। अब मैं आईएफएससी-संबंधी मुद्दों के बारे में बात करना चाहूंगा।

सी. माइक्रो ईकोसिस्टम

15. जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि गिफ्ट के लिए तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है आईएफएससी के भीतर माइक्रो ईको सिस्टम। यहां एक पूरक आधुनिक कानूनी बुनियादी सुविधा की जरूरत है। हमें इस संबंध में बहुत कुछ करना है। हमें क़ानूनी ढांचे को मज़बूत करना होगा जो उन संस्थाओं के लिए लागू हों जो शहर

में स्वयं कार्य कर रही हैं तथा घरेलू क्षेत्र में उनके प्रतिपक्षी भी कार्य कर रहे हैं। यह संभव है कि अनेक कारोबारी संस्थाएं जो अच्छी तरह से गिफ्ट शहर में लाकर स्थापित की जा सकती हैं उन्हें इस तरह के ढांचे के लागू होने का इंतज़ार है।

16. आईएफएससी के पास ऐसा क़ानूनी ढांचा होना चाहिए जो जटिल स्वरूप की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संविदाओं के निपटान/लागू करने में उत्पन्न संघर्षों एवं विवादों का तेजी से निपटान कर सकें। संविदाएं अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप होनी चाहिए तथा न्यायालय में ले जाने योग्य होनी चाहिए एवं हो सके तो आईएसडीए के समान उनका प्रलेखीकरण किया जाना चाहिए।

17. भारत में जिन क़ानूनों से वित्तीय संविदाएं संचालित होती हैं उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा उनमें जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। समीक्षा के आधार पर गिफ्ट में एक विश्व स्तरीय कानूनी ढांचा लागू किया जाना चाहिए, चाहे वित्तीय संविदाओं को संचालित करने वाले वर्तमान क़ानून में उपयुक्त संशोधन करके या फिर नया क़ानून पारित करके। दोनों में से किसी बी तरह इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए, भले ही इस अंतराल को दूर करने केलिए मिशन के तौर पर एक शहर में वित्तीय संस्थाओं का बेहतर रेगुलेशन एवं पर्यवेक्षण हो सकेगा। जहां प्रत्येक रेगुलेटर प्रारंभ में जब कारोबार छोटे स्तर पर हो तो उनका पर्यवेक्षण करें, वहीं एकीकृत रेगुलेटर के लिए आवश्यक होगा कि वह आईएफएससी की ओर पूर-पूरा ध्यान दे। इस प्रकार की संरचना के डिजाइन का कार्य यथशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए ताकि हम उसे समय पर लागू कर सकें।

19. अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजकोषीय प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएं गिफ्ट शहर को इस मुकाम से आगे ले जाएंगी, जिन कार्यक्षेत्रों के बारे में मैंने सुझाव दिया है वे आवश्यक हैं, उन्हीं से आईएफएससी कारोबार की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सकेगा।